a view to achieving the following objectives:—

1. Assisting entrepreneurs to identify joint venture and technology partners from other countries.
2. Networking of focal points throughout India of public and private sector institutions, active in promotion of business cooperation between Indian firms and foreign firms.
3. Increasing the awareness of services available from UNIDO and its investment promotion services in developed and developing countries in the area of investment project identification, formulation, screening and evaluation.
4. Organising INTECHMARTs for technology and investment matchmaking at the State-level.
5. Following up the projects identified for joint venture in the previous INTECHMARTs held at New Delhi in 1995 and 1996.

The Project is for a period of two years starting from 1st May, 1996. The ITPI Project is mainly to promote cooperation between small and medium enterprises for technology transfer and joint ventures. This will contribute to small and medium enterprises development, which in turn will lead to skills upgradation and employment generation having, thus, diret impact on poverty alleviation programme.

अनुसूचित जनजातियों का विलुप्त होना

2731. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आने वाली जातियों में से कुछ जातियां विलुप्त हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात हेतु कोयले की मांग और आपूर्ति

2732. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सरकार को इसके विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले की प्रतिवर्ष कितनी मात्रा की आवश्यकता है और इसका जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसकी मांग और आपूर्ति में बड़ा भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (घ) कोयले की आवश्यकताओं का समग्र देश के लिए उद्योगवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन किया जाता है। इनका मूल्यांकन राज्यवार अथवा जिलावार नहीं किया जाता है। किंतु, कोयला कंपनियों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था उन्हें दिए गए संयोजनों/प्रायोजनों तथा उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। उच्चतम प्राथमिकता के परिणामस्वरूप, जो कि विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मामले में दी जाती है, और कोयले की मांग में इस क्षेत्र से तेजी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विद्युत क्षेत्र के अलावा, उपभोक्ताओं को की गई कुल आपूर्ति, जिसमें गुजरात की औद्योगिक तथा एस०एस०आई० यूनिटें शामिल हैं, वर्ष 1995-96 में 25.76 लाख टन (अनंतिम) की आपूर्ति की गई, जबकि 1994-95 में यह 32.16 लाख टन (अनंतिम) थी। किन्तु, गुजरात के विद्युत क्षेत्र को किया गया कुल प्रेषण में 125.84 लाख टन (अनंतिम) तक की वृद्धि हो गई, जबकि 1994-95 में प्रेषण 118.88 लाख टन (अनंतिम) था।

कोयला कंपनियां देश में सभी उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने का कोयले का उत्पादन करके प्रयास कर रही है, जिसमें गुजरात के उपभोक्ता भी शामिल हैं। इसके अलावा, कई कोलियरियों से उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयले की पेशकश भी की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना संयोजनों/प्रायोजनों की